प्रदेश राज्य में वास्तविक विद्युत आपूर्ति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(सभी आंकड़े मि.यू. निवल में)

	अप्रैल–अक्तूबर, 1993
आवश्यकता	12355
उपलब्धता	11765
कमी	590
(%)	(4.8)

वर्तमान में इस राज्य में उद्योगों पर कोई भी विद्युत कटौती लागू नहीं है तथा कृषि क्षेत्र को प्रतिदिन लगभग 20 घंटे (औसत) के लिए बिजली दी जा रही है।

(ख) इसके अपने उत्पादन के अलावा मध्य प्रदेश केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों से अपना और तथा पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्रों के केन्द्रों से अनाबंटित 15% से सहायता प्राप्त कर रहा है। इस समय, मध्य प्रदेश बालको, आरएसपी, दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली के लिए 83 मे.वा. के विशिष्ट आबंटन को लेखे में लेने के पश्चात् केन्द्रीय क्षेत्र के अनाबंटित उत्पादन में से 40% आबंटित किया जाता है । मध्य प्रदेश ने निकटवर्ती राज्यों प्रणालियों से दिन प्रतिदिन उपलब्धता पर निर्भर करते हुए सहायता भी प्राप्त की है । अप्रैल-अक्तूबर, 1993 की अवधि के दौरान पश्चिमी क्षेत्र और निकटवर्ती प्रणालियों के केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से निमत मात्रा की अपेक्षा वास्तविक आहरण के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत हैं :—

(सभी आंकड़े जल मि. यू. में)

	अप्रैल–अक्तूबर, 1793	
	नियत मात्रा	वास्तविक आहरण
पश्चिमी क्षेत्र में		
केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्र	4734.2	5387.5
राजस्थान	——	159.1
उत्तरी ग्रिड	—	16.5

(ग) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित आठवीं योजना विद्युत कार्यक्रम के अनुसार 1994–95 के अन्त तक मध्य प्रदेश में प्रत्याशित शिखर कमी तथा ऊर्जा कमी 22.2% तथा 9.6% होगी।

(घ) मध्य प्रदेश में विद्युत कमी परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए विद्युत उपलब्धता में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जोकि ये है–नव उत्पादन क्षमता के प्रचालन में तेजी लाना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन को सुधारना, पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करना, मांग प्रबन्ध तथा ऊर्जा संरक्षण उपायों का कार्यान्वयन तथा कमी वाले क्षेत्रों को बचत वाले क्षेत्रों से ऊर्जा अन्तरित करना। समय-समय पर पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों के अनाबंटित उत्पादन मे सहायता उपलब्ध करवाना। आठवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में 2351 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि का प्रस्ताव है । इसके अलावा यह राज्य केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं तथा पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित की जा रही संयुक्त उपक्रम परियोजनाओं से अपना शेयर प्राप्त करेगा ।

Recommendatoicns of K. P. Rao Committee

590 SHRI KAMAL MORARKA: .of POWER be pleated to statij;

(a) whether it is a fact that the K. P. Rao Committee has recommended fiscal incentives for promoting bulk energy conservation;

(b) if so, the details of the recommendations; and

(c) whether Government have considered the recommendations; and mendations;

(d) if so, the decision taken there on?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOWER (SHRI P. V, RANGAYYA NAIDU): (a) to (d) The K. P. Rao Committee was set up to suggest principles and normative parameters for working out

the tariff for sale of power Generating Stations of the National Thermal Power Corporation and the National Hydro Electric Power Corporation. The report of the Committee was accepted by the Government and the tariffs of NTPC and NHPC stations are being fixed on the basis of the recommendations of the K. P. Rao Committee Report.

Power shortage in the States

591. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of POWER- be pleased to state:

(a) the magnitude of power shortage being experienced by each State;

(b) the reasons for deficiency in power supply in these States;

(c) the steps taken by Government to improve the power supply position;

(d) whether it is a fact that Government propose to set up a National Grid for balanced Power distribution in the country; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI . V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) State wise power supply position during April, 1993 to October, is given in the Statement (See below) The main reason for power shortage in various States is due to *demand-out-stripping the availability of power, constraints of funds with power utitlise, unsatisfactory performance of some Thermal Power stations due to short receipt of coal, system constraints etc.

(e) Various measures being taken to improve the availability of power in the country include (i) expediting commissioning of new generating[1] ce.pacity (ii) implementation of short gestation projects (iii) Improving the performance of existing power stations (iv) Reduction of Transmission and Distribution losses, (v) Implementation of demand management and energy conservation measures and (vi) arranging transfer of energy from surplus to deficit areas etc.

(d) and (e) Yes Sir, setting up of the National Power grid is an evolutionary process which envisages strengthening of the existing regional power grids and their progressive integration through inter-state|inter-rogional transmission lines. The Nation Grid will enable optimum utilisation of existing resources and permit power transfer from one region to another..

Statement

Actual Power Supply Position for April 93— *October* 93!

(Figures in MU net)

Region/State/System	April, 93 —October 93			
	Requirement	Availability	Shortage	(%)
Northern Region :				
Chandigarh	422	422	0	0.0%
Delhi	6685	6571	114	1.7%
Haryana	7025	6499	526	7.5%